



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2005/आषाढ़ 15, 1927

No. 697]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2005/ASADHA 15, 1927

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2005

का.आ. 955(अ).—जबकि 5,00,000 रु. (पांच लाख रुपए मात्र) तथा 3,77,624 रु. ब्याज (तीन लाख सतहत्तर हजार छः सौ चौबीस रुपए मात्र) नवल ग्रामोद्योग समिति, जो कि एक पंजीकृत समिति है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राम-आसिफाबाद नारंगपुर, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) में है, के द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (यहां इसके बाद उक्त आयोग के रूप में उल्लिखित है) को देय है।

और जबकि, उक्त नवल ग्रामोद्योग समिति ने 5,00,000 रु. (पांच लाख रुपए मात्र) तथा 3,77,624 रु. ब्याज (तीन लाख सतहत्तर हजार छः सौ चौबीस रुपए मात्र) की धनराशि का उक्त आयोग को भुगतान करने की देयता पर विवाद किया है और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक दीवानी समादेश याचिका सं. 2004 की 47350 दायर की है तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 नवम्बर, 2004 के आदेश में निदेश दिया कि मध्यस्थता कार्यवाही आरंभ की जाए और तदनुसार आदेश पारित किया जाए और उक्त कार्यवाई तीन महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।

अब इसलिए खादी और ग्रामोद्योग नियमावली, 1957 के नियम 25ख के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केंद्र सरकार श्री प्रवीन महतो, अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार, विकास आयुक्त कार्यालय (ल. उ.), लघु उद्योग मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 की अध्यक्षता में एक व्यक्ति को एक न्यायाधिकरण गठित करती है और उक्त अधिनियम की धारा 19ख की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयोग को नवल ग्रामोद्योग समिति, ग्राम-आसिफाबाद, नारंगपुर, मेरठ (उत्तर प्रदेश) द्वारा बकायों के भुगतान के बारे में निर्णय लेने के लिए विवादित प्रश्न को उक्त न्यायाधिकरण को भेजती है।

न्यायाधिकरण अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को यथासंभव प्रस्तुत करेगी किन्तु यह प्रस्तुति इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के बाद नहीं होनी चाहिए। न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

इस अधिसूचना का अनुमोदन कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री द्वारा किया गया है।

[फा. सं. सी-18019/5/2001-केवीआई]

ए. पी. पादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2005

S.O. 955(E).—Whereas a sum of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh only) plus interest of Rs. 3,77,624 (Rupees Three lakh seventy seven thousand six hundred twenty four only) is payable by 'Naval Gramodyog Samiti', a registered society having its registered office at Vill-Asifabad Narangpur, Distt. Meerut, (Uttar Pradesh) to the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter referred to as the said Commission);

And whereas, the said Naval Gramodyog Samiti has disputed its liability to pay the said sum of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh) plus interest of Rs. 3,77,624 (Rupees Three lakh seventy seven thousand six hundred twenty four only) to the said commission and filed a Civil Miscellaneous Writ Petition No. 47350 of 2004 before the High Court, Allahabad and the High Court of Allahabad vide Order dated the 22nd November, 2004 directed that the arbitration proceedings be initiated and the order be passed accordingly and that the said exercise should be completed within three months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 25B of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri Praveen Mahto, Additional Economic Adviser, Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), Ministry of Small Scale Industries, Nirman Bhavan, New Delhi-110011 and refers the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues by the Naval Gramodyog Samiti, Vill-Asifabad Narangpur, Meerut (Uttar Pradesh) to the said Commission within the meaning of Sub-section (1) of Section 19B of the said Act.

The Tribunal shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The headquarters of the Tribunal shall be at New Delhi.

This has the approval of Minister of Agro and Rural Industries.

[F. No. C-18019/5/2001-KV1]

A. P. PADHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2005

का.आ. 956(अ).—जबकि 7,10,000 रु. (सात लाख दस हजार रुपए मात्र) ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज 3,79,499.06 (तीन लाख उन्नहत्तर हजार चार सौ निन्नयानवे और छः पैसा) दिनांक 24 जनवरी, 2005 को ग्रामीण समाज कल्याण समिति बेदपुरपिरन, कलियार, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश जो कि एक पंजीकृत समिति है और उनका पंजीकृत कार्यालय बेदपुरपिरन, कलियार, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में है, के द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (यहां इसके बाद उक्त आयोग के रूप में उल्लिखित है) को देय है।

और जबकि, उक्त ग्रामीण समाज कल्याण समिति ने 7,10,000 रु. (सात लाख दस हजार रुपए मात्र) तथा ब्याज और दंडात्मक ब्याज 3,79,499.06 (तीन लाख उनासी हजार चार सौ निन्नयानवे और छः पैसा) की धनराशि का उक्त आयोग को भुगतान की देयता पर विवाद किया है और जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के समक्ष विविध आवेदन संख्या 8/0 दायर की जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मामले को न्यायाधिकरण में ले जाने के संबंध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख की उप-धारा (2) को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 04 जून, 2004 के अपने आदेश में निदेश दिया था कि मामले को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख की उप-धारा (2) के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु भेजा जाए। नैनीताल स्थित माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 2004 का 838 (एम/एस) में दिनांक 13 सितम्बर, 2004 के आदेश में निदेश दिया गया है कि मामले को न्यायाधिकरण में भेजा जाए और न्यायाधिकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर उक्त मामले में निर्णय देगा।

अब इसलिए खादी और ग्रामोद्योग नियमावली, 1957 के नियम 25ख के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केंद्र सरकार श्री प्रवीन महतो, अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार, विकास आयुक्त कार्यालय (ल. उ.), लघु उद्योग मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 की अध्यक्षता में एक व्यक्ति का एक न्यायाधिकरण गठित करती है और उक्त अधिनियम की धारा 19ख की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयोग को ग्रामीण समाज कल्याण समिति बेदपुरपिरन, कलियार, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश द्वारा बकायों के भुगतान के बारे में निर्णय लेने के लिए विवादित प्रश्न को उक्त न्यायाधिकरण को भेजती है।

न्यायाधिकरण अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को यथासंभव शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करेगी किन्तु यह प्रस्तुति इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह के बाद नहीं होनी चाहिए। न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

इस अधिसूचना का अनुमोदन कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री द्वारा किया गया है।

[फा. सं. सी-18019/5/2001-केवीआई]

ए. पी. पाढ़ी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2005

S.O. 956(E).—Whereas a sum of Rs. 7,10,000/- (Rupees seven lakh and ten thousand only) plus interest and penal interest of Rs. 3,79,499.06 (Rupees three lakh seventy nine thousand four hundred ninety nine and paise six only) due as on the 24th January, 2005 is payable by 'Grameen Samaj Kalyan Samiti, Bedpurpiran, Kaliyar, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar, Uttar Pradesh', a registered society having its registered office at Bedpurpiran, Kaliyar, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar in Uttar Pradesh to the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter referred to as the said Commission);

And whereas, the said Grameen Samaj Kalyan Samiti has disputed its liability to pay the said sum of Rs. 7,10,000/- (Rupees seven lakh and ten thousand only) plus interest and penal interest of Rs. 3,79,499.06 (Rupees three lakh seventy nine thousand four hundred ninety nine and paise six only) to the said Commission and filed a miscellaneous application No. 8/0 before the District Magistrate, Haridwar, praying for invocation of Sub-section (2) of Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) for referring the matter to the Tribunal. The District Magistrate vide his Order dated the 4th June, 2004 directed that the matter may be referred under Sub-section (2) of Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) for decision before the Tribunal. The Hon'ble High Court of Uttaranchal at Nainital vide Order dated the 13th September, 2004 in the Writ Petition No. 838 of 2004 (M/s.) has also directed that the matter may be referred to the Tribunal and that the Tribunal shall decide the same within six weeks from the date of filing of the copy of the order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 25B of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri Praveen Mahto, Additional Economic Adviser, Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), Ministry of Small Scale Industries, Nirman Bhavan, New Delhi-110011 and refers the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues by the Grameen Samaj Kalyan Samiti Bedpurpiran Kaliyar, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar, (Uttar Pradesh) to the said Commission within the meaning of Sub-section (1) of Section 19B of the said Act.

The Tribunal shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than six weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The headquarters of the Tribunal shall be at New Delhi.

This has the approval of Minister of Agro and Rural Industries.

[F.No. C-18019/5/2001-KVI]

A. P. PADHI, Jt. Secy.